संपादकीय

राजनीतिक मतभेद भुला प्राथमिकताएं तय हों

यह विडंबना ही है कि पंजाब में आसन्न चुनौतियों को नजरअदांज करके राजनीतिक लाभ के लिये गैरजरूरी गतिविधियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मान सरकार द्वारा विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मामला दर्ज करना, एक अनाश्यक राजनीतिक उकसावा ही कहा जाएगा। निश्चित रूप से यह प्रकरण एक अनुचित समय पर हुआ है। आज एक बार फिर पंजाब दोराहे पर खड़ा है, जहां उसे उन ताकतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने अतीत में राज्य को भयावह संकट में धकेल कर अमन-शांति को ग्रहण लगाया था। इन ताकतों के खतरनाक मंसूबों को गंभीरता से महसूस किया जाना चाहिए। हाल के दिनों में ग्रेनेड हमलों की शृंखला शासन-प्रशासन के साथ आम लोगों को व्यथित किए हुए है। ऐसी किसी भी आतंकी गतिविधि के खिलाफ समय रहते सामूहिक संकल्प लेने की सख्त जरूरत है। इस वक्त पंजाब के राजनीतिक परिदृश्य में जिम्मेदार नेतृत्व की सख्त जरूरत है। यह समय नहीं है कि राजनीतिक लाभ-हानि के गणित को दृष्टिगत रखकर एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिखाई जाए। यदि पंजाब में सिर उठा रही आतंकवाद की नई चुनौती के खतरे को गंभीरता से लेने की बजाय, अभद्र भाषा की टिप्पणियों को प्राथमिकता दी जाएगी तो राज्य का बहुत कुछ दांव पर लगेगा। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि इस राजनीतिक विवाद में पुलिस को घसीटा जा रहा है। ऐसे चुनौती वाले समय में जब पुलिस का मनोबल बढ़ाकर उसकी पूरी ऊर्जा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर केंद्रित करने की जरूरत है, जो राज्य को फिर से अतीत के उस काले दौर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उबरने में पंजाब के लोगों ने भारी कीमत चुकाई थी। कोई नहीं चाहेगा कि राज्य को फिर उस भयावह दौर से गुजरना पड़े। इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के समक्ष मौजूदा चुनौतियों और हिंसक अतीत को दृष्टिगत रखते हुए राजनीति प्रतिष्ठानों से संवेदनशील मामलों में संयमित और सावधान प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन विडंबना है कि नये सिरे से पंजाब की शांति को भंग करने की कुत्सित कोशिशों के प्रति राजनीतिक दलों द्वारा गंभीर प्रतिसाद नहीं दिया जा रहा है। हाल के दिनों में राज्य में सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की सतही बयानबाजी से तो ऐसा नहीं लगता है कि राजनेताओं द्वारा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में परिपक्ता का व्यवहार किया जा रहा हो। सवाल है कि क्या कांग्रेस नेता बाजवा को अपने बयानों को अभिव्यक्त करने में अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए था? निःसंदेह उन्हें गंभीरता व परिपक्ता का परिचय देना चाहिए था। सवाल यह भी है कि उनके बयानों के जबाव में क्या सरकार की ओर से मामला दर्ज किया जाना चाहिए था।

विनोद शर्मा, संपादक

मोदी का नया मंत्र- देरी विकास का दुश्मन

आज की दुनिया के विकास का ईंधन एक तरह से जैविक ऊर्जा यानी पेट्रोल और डीजल है। अरब देशों के आपसी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत को पेट्रोलियम आपूर्ति में बाधा न पड़ना, चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापार युद्ध के बावजूद भारत की विकास दर में कमी ना आना, एक तरह के भारत के संकल्प का नतीजा है। बेशक इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका श्रेय युवाओं को दिया। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी युवाओं की महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित है। इससे दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। पहले दुनिया मानती थी कि भारत धीरे-धीरे और लगातार प्रगति करेगा, उसी दुनिया को भारत अलग नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो दुनिया अब देश को 'तेज और निडर भारत' के रूप में देख रही है। परियोजनाओं में देरी को विकास के दुश्मन के तौर पर प्रधानमंत्री का स्थापित करना एक तरह से राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को संबोधित करना है। विश्व गुरू बनने की आकांक्षा हो या आर्थिक या दूसरी तरह वैश्विक महाशक्ति बनना।

उमेश चतुर्वेदी

लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र की इस खामी को समझा था। सबसे पहले इस कमजोरी पर काबू पाने की उन्होंने गुजरात में कोशिश की और देश की कमान संभालने के बाद उन्होंने तंत्र से इस खामी को दूर करने की कोशिश की। अमेरिकी लेखक जय एम फिनमैन की अमेरिकी बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर कुछ साल पहले एक पुस्तक आई थी, डिले, डिनाय, डिफेंड...अंग्रेजी के इन तीन शब्दों का अर्थ है टालना, इनकार करना और बचाव करना। इस पुस्तक में फिनमैन ने साबित किया है कि किस तरह बीमा कंपनियां दावों को टालती हैं, देने से इनकार करती हैं और फिर अपने फैसले का बचाव करती हैं। नौकरशाही से जिनका पल्ला पड़ता रहता है, उन्हें भी पता है कि नौकरशाही किस तरह फैसलों को टालती हैं, उनके हिसाब से योजना नहीं हुई तो उससे आगे बढ़ाने से इनकार कर देती है और आखिर में उस योजना का पलीता ही लगा देती है। इस देर और इनकार की कीमत आखिरकार जनता को चुकानी पड़ती है। अव्वल तो तय समय पर लोगों को सहूलियतें मिल ही नहीं पाती। लेकिन जब किसी वजह से परियोजना पर काम चलता भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी लागत खर्च बढ़ चुकी होती है। आखिरकार इसकी कीमत देश को ही चुकानी पड़ती है। लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री मोदी ने तंत्र की इस खामी को समझा था। सबसे पहले इस कमजोरी पर काबू पाने की उन्होंने गुजरात में कोशिश की और देश की कमान संभालने के बाद उन्होंने तंत्र से इस खामी को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का यह कहना कि देरी विकास का दुश्मन है और हमारी सरकार इस दुश्मन को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी इसी सोच को जाहिर करता है।

बीते दिनों एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं में देरी को देश के विकास की बड़ा रोड़ा बताया है। अपने संबोधन में उन्होंने स्वीकार किया परियोजनाओं में देरी से प्रगति बाधित होती है, जबकि तात्कालिक कार्रवाई से विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में असम के बोगीबील पुल परियोजन का उदाहरण दिया, जिसकी आधारशिला 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रखी थी, बाद में सत्ता संभालते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका काम शुरू कराया। लेकिन बाद की सरकारों के दौरान पता नहीं किन वजहों से इस परियोजना का काम रोक दिया गया। जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश और असम के लाखों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ीं। इस योजना पर दोबारा काम मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ और चार साल में यह पुल बनकर तैयार हुआ और 2018 इसे जनता के लिए खोला गया। अगर इसी हिसाब से देखें तो यह काम 2001 या अधिक से अधिक 2002 में पूरा किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सत्ताएं बदलते ही कई योजनाएं रोक दी जाती हैं और राजनीतिक नफा-नुकसान को देखते हुए उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। केरल की कोल्लम बाईपास सड़क परियोजना को इसके उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। यह योजना 1972 में शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हुई। तकरीबन पचास साल तक यह योजना लटकी रही। यह बात और है कि इस काम को मोदी सरकार ने ही पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या देश के सामने कोई लक्ष्य रखते हैं, तो वे नया नारा भी गढ़ते हैं। 'देरी विकास का दुश्मन है' इस कड़ी में नया नारा है। देश में ऐसी कई परियोजनाएं मिल जाएंगी, जिन्हें तय वक्त तक पूरा नहीं किया जा सका। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर मांझी में एक पुल है। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने इस पुल को केंद्र मे रखकर कविता ही रच डाली है। इस पुल का शिलान्यास जनता पार्टी के शासनकाल के राज्य मंत्री चांद राम ने शुरू किया और दशकों तक इसका काम नहीं हो पाया। अरसे बाद यह पुल बनकर तैयार हो पाया। परियोजनाओं में देरी की ऐसी ढेरों कहानियां पूरे देश में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना का भी इसी संदर्भ में उल्लेख किया है। देश की आर्थिक राजधानी के लिए बेहतर और सुगम हवाई सेवा की जरूरत से किसे इनकार हो सकता है। लेकिन नवी मुंबई में हवाई अड्डा बनाने की चर्चा साल 1997 में शुरू हुई। लेकिन उस परियोजना को ठीक दस साल बाद यानी 2007 में मंजूरी मिल पाई। लेकिन राजनीति और नौकरशाही से कोलाज वाले तंत्र की वजह से इस परियोजना पर ठोस रूप में काम नहीं हो पाया। प्रधानमत्री ने तो सीधे-सीधे इसके लिए इस दौरान केंद्र और महाराष्ट्र में काबिज रही कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री के अनुसार, कांग्रेस की सरकारों ने इस परियोजना में ना तो दिलचस्पी दिखाई, ना ही कोई कार्रवाई नहीं की। यह बात और है कि मोदी सरकार ने इस परियोजना के कामकाज में तेजी लाने की दिशा आगे बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह दूसरी योजनाएं तेज गति से तय वक्त या उससे पहले पूरी हुई, उसी गति और तेजी से नवी मुंबई हवाई अड्डा परियोजना भी पूरा होगी। देश के आर्थिक विकास की नींव नरसिंह राव ने साल 1991 में रखी थी, जिनके सहयोग से तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की गति को तेज किया था। देश की आर्थिकी को लाइसेंस राज और लालफीताशाही से दूर किया था। उस बदलाव का असर भी दिखा। लेकिन राजकाज की कमान जिस तंत्र के हाथों में रही, वह पुरानी मानसिकता से ग्रस्त रहा। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद इस मानसिकता को थोड़ी लगाम जरूर लगी है। यह बात और है कि इस मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 'देरी, विकास का दुश्मन है' के प्रधानमंत्री के नए मंत्र का ही असर कहा जाएगा कि आर्थिक मोर्चे पर तय लक्ष्यों को हासिल करना आसान हुआ। आर्थिक मोर्चे पर बदलाव का ही असर है कि कुछ ही वर्षों में दुनिया की 11वें नंबर से भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनियाभर की विकास दर को कोरोना की महामारी ने बुरी तरह प्रभावित किया।

चेन्नई के खराब प्रदर्शन से धोनी की फिटनेस पर उठ रहे सवाल

आदर्श प्रकाश सिंह

चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल की मजबूत टीम माना जाता है जिसने अब तक 5 बार यह खिताब जीता है। देश के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी इस टीम के साथ आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। वह 43 साल के हो चुके हैं पर, अब भी खेल रहे हैं। आईपीएल के 18वें सत्र में अब तक खेले गए मैचों में कई बातें उभर कर आई हैं। पिछले साल की तीन मजबूत टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की हालत इस बार पतली है जबकि गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन काबिलेतारीफ है। वहीं सबसे महंगे बिके विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको बता दें कि पंत को इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा है। पहले बात करते हैं चेन्नई की टीम की। यह टीम अपने घर में तीन मैच हार चुकी है। इस नाते महेन्द्र सिंह धोनी की फिटनेस पर सवाल उठने लगे हैं। भारत के पूर्व कप्तान धोनी जुलाई में 44 साल के हो जाएंगे। इतनी उम्र के बावजूद वह आईपीएल में खेलना जारी रखे हुए हैं। दो साल पहले उन्होंने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी थी। युवा रुतुराज गायकवाड़ चेन्नई के नए कप्तान बनाए गए। पर, मौजूदा सत्र के बीच चोटिल होने के कारण उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी। फिर से धोनी के कंधों पर नेतृत्व का भार आन पड़ा है। मगर, उनकी कप्तानी में भी चेन्नई को शुक्रवार को कोलकाता से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। पांच बार की चैम्पियन रही यह टीम अब तक 7 मैचों में से 5 हार चुकी है। शुरुआती एक मैच जीतने के बाद से धोनी के वर्चस्व वाली यह टीम लगातार पराजय का सामना कर रही है। धोनी की वजह से पीली जर्सी वाली चेन्नई टीम के प्रशंसक करोड़ों में हैं लेकिन अब उनमें निराशा का भाव जाग गया है। भारत के क्रिकेट इतिहास में आईपीएल की लोकप्रियता चरम पर है। हर साल गर्मियों में होने वाले इस टूर्नामेंट में देश की प्रतिष्ठा भले ही दांव पर न हो लेकिन खिलाड़ियों को मालामाल करने के लिए यह काफी है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग देश का एक ब्रांड बन चुका है। स्टेडियम में आने वाली भीड़ अपने चहेते खिलाड़ियों को चौके छक्के लगाते देखना चाहती है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल की मजबूत टीम माना जाता है जिसने अब तक 5 बार यह खिताब जीता है। देश के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी इस टीम के साथ आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। वह 43 साल के हो चुके हैं पर, अब भी खेल रहे हैं। हर बार लगता है कि यह धोनी का आखिरी साल है लेकिन उनके करोड़ों प्रशंसक उन्हें रिटायर नहीं होने दे रहे। 2025 का आईपीएल उनका आखिरी है या नहीं, यह कोई नहीं बता सकता। पर, उनके निराशाजनक प्रदर्शन से रिटायरमेंट को लेकर फिर चर्चा छिड़ गई है। बल्लेबाजी के लिए धोनी का काफी नीचे आना भी सवाल खड़े करता है। जब वह सातवें या आठवें नंबर पर आते हैं तब गेंदें कम बचती हैं। ऐसे में जीत दिलाने के लिए उनकी कोशिश बेकार चली जाती है।सोमवार 14 अप्रैल को लखनऊ में खेला गया मैच चेन्नई ने अवश्य जीत लिया लेकिन अब भी अंक तालिका में धोनी की टीम आखिरी पायदान पर है। सात में से केवल दो मैचों में चेन्नई को जीत मिली है। ऐसे में नहीं लगता कि सीएसके चोटी की चार टीमों में पहुंच पाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपने घरेलू मैदान में पांच विकेट से हार गई। मेजबान टीम से ज्यादा यहां पीली जर्सी वाले प्रशंसक अधिक दिख रहे थे। इसकी एकमात्र वजह महेन्द्र सिंह धोनी हैं जिन्हें खेलते देखने के लिए दर्शक बेताब रहते हैं। धोनी कहीं भी खेल रहे हों उन्हें देखने का क्रेज बरकरार रहता है। मगर, देखने की बात यही है कि वह कब तक खेलेंगे? लखनऊ में धोनी ने 26 रन ही बनाए लेकिन उनके बल्ले से निकले 4 चौके और एक छक्के से इकाना स्टेडियम रोमांचित हो गया। इसी मुकाबले में लखनऊ टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने इस आईपीएल में पहली बार अर्धशतक बनाया। उनकी नाकामी से टीम पर दबाव पड़ रहा था। पंत की विफलता से टीम प्रबंधन चिंतित भी था। कप्तान के असफल होने से टीम के मनोबल पर असर पड़ता है। उन्होंने 63 रनों की पारी खेली। हालांकि, अपनी टीम को जिता नहीं पाए। अभी तक खेले गए मैचों के हिसाब से पंत की टीम चौथे नंबर पर है। उसने 7 में से 4 मैच जीते हैं। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन इस टीम के दमदार खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। दिल्ली की टीम नए कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

मुर्शिदाबाद दंगा, एसएससी स्कैम, टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई

अभिनय आकाश

तीन दशक तक पुराने लेफ्ट फ्रंट को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से कैसे उखाड़ फेका ये अपने आप में एक केस स्टडी है। लेकिन अब इतने साल बाद लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल संभालना मुश्किल हो गया है। बीते एक हफ्ते से जो हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है, ममता बनर्जी उसे रोकने में नाकाबिल लग रही हैं। वक्त बीतने के साथ ब्यौरे धुंधले पड़ने लगते हैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम है लेकिन एक जख्म है सांप्रदायिकता का जिसे कोई भी भर नहीं पा रहा। एक भीड़ है जो इस देश की छाती पर चढ़ गई है और दम घोंटने की भरसक कोशिश कर रही है। नफरत, हिंसा, विध्वंस और अराजकता इस भीड़ की डिक्शनरी में सिर्फ यही शब्द हैं। बीते 11 अप्रैल को ये उन्मादी भीड़ पश्चिम बंगाल में निकली। दुकाने लूटी, गाड़ियां जलाई, हत्याएं की। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए और पुलिस प्रशासन भी मजबूर नजर आया। तीन दिन तक हिंसा का नंगा नाच चलता रहा और राजनीति भी बदस्तूर चलती रही। आज बात पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के खिलाफ शुरू हुए हिंसका विरोध प्रदर्शन की करेंगे। जिसने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे में यूं तो वक्फ बिल का विरोध 8 अप्रैल से चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अचानक माहौल बिगड़ा। करीब 150 लोगों ने मोहल्ले में हमला कर दिया। घरों-दुकानों में आग लगा दी। पुरुषों को पीटा। आंखों के सामने बेटियों की आबरू लूटने की कोशिश की। उन्होंने धमकी दी भाग जाओ, वरना मारे जाओगे। मैं बच्चों को लेकर भागी। इतना कहते-कहते 51 साल की जानकी मंडल फूट-फूट कर रोने लगीं। वो अभी मालदा के वैष्णवनगर के एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। 40 हिंदू परिवार यहीं रुके हैं। कुछ यही कहानी शमशेरगंज में प्रसेनजीत दास ने बताई। मुर्शिदाबाद हिंसा में कुल 3 मौतें हुई हैं, इनमें प्रसेनजीत दास का चचेरा भाई हरगोविंद दास और भतीजा चंदन भी शामिल है। प्रसेनजीत ने बताया कि 18 अप्रैल की रात करीब 400 लोगों की भीड़ तलवारों और छुरियां लहराते मोहल्ले में घुसी। उन्होंने 25 से 30 घरों, होटलों, दुकानों में तोड़फोड़ की। आग लगा दी। भीड़ बहुत उग्र थी, इसलिए हम लोग उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि ममता बनर्जी एक प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं कर पाती हैं। क्या ममता बनर्जी को मालूम नहीं था कि वक्फ एक्ट पास होने के बाद उनके राज्य में क्या होगा? एक बात को साफ है चाहे आप हिंदू हो मुसलमान या किसी और धर्म के अगर आप शांति पूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते तो आपको प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। बंगाल में भी कश्मीर पैटर्न दिखाया गया। कैसे शुक्रवार की नमाज होती है और फिर लोग बाहर आते हैं और पथराव शुरू हो जाता है। बीडीओ ऑफिस पर पथराव किया गया। अब इन्हें भला कौन समझाए कि बीडिओ ऑफिस पर पथराव करके क्या वक्फ एक्ट वापस हो जाएगा। रेलवे गेटवे पर अटैक और एक रिटेल चेन को लूटा गया। अब आप ही बताओ की रिटेल चेन और वक्फ कानून में क्या समानता है? तीन दशक तक पुराने लेफ्ट फ्रंट को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से कैसे उखाड़ फेका ये अपने आप में एक केस स्टडी है। लेकिन अब इतने साल बाद लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल संभालना मुश्किल हो गया है। बीते एक हफ्ते से जो हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है, ममता बनर्जी उसे रोकने में नाकाबिल लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी राजनीति को समझते हुए जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। क्या ये कोई तुष्टीकरण है या फिर टीएमसी में इतना करप्शन ममता पश्चिम बंगाल पर अपना कंट्रोल खो दिया। लोगों का गुस्सा अब धीरे धीरे ममता बनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। एक साल बंगाल के चुनाव में रह गया है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के जाने से पहले उनका भी एक साल जैसे हालात थे। वैसे ही वर्तमान के हालात होते नजर आ रहे हैं। हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाथ जोड़कर कहती हैं कि वायलेंस को बढ़ावा मत नहीं दीजिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से तनाव के बीच शांति बनाए रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मरते हैं तो लड़ाई क्यों? दंगे, युद्ध या अशांति क्यों? केंद्र का कानून है इसे हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब ममता बनर्जी की पुलिस इस दंगे को रोकने की काबिलियत नहीं थी? टीएमसी का सीधा सा स्टैंड है कि ये दंगा हमने नहीं किया है, कैसे हो गया, ये बाहर से लोग आए हैं। टीएमसी के सपोर्टर्स वीडियो जारी कर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं और आसपास के जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात होनी शुरू हो गई है। अब अगर आप बेसिक लॉ एंड ऑर्डर भी अपने राज्य में मैनेज नहीं कर पाओगे तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू अब अपने देश में ही पलायन कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर में बांधकर रखा गया है कलश

महाभारत काल से जुड़ा है इसका इतिहास

अनन्या मिश्रा

हिमाचल प्रदेश के शिमला से 130 किमी की दूरी पर हाटेश्वरी माता का मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के पव?बर नदी के किनारे बसा एक प्राचीन गांव है। इस मंदिर में दूर-दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां पर अक्सर लोग घूमने-फिरने जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसे कई फेमस और प्राचीन मंदिर हैं, जिससे जुड़ी कई स्थानीय मान्यताएं और लोककथाएं मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में एक हाटेश्वरी मंदिर है, जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ माना जाता है। जिसके साक्ष्य आज भी मंदिर में देखने को मिलते हैं। हालांकि इस मंदिर के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से 130 किमी की दूरी पर हाटेश्वरी माता का मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के पब्बर नदी के किनारे बसा एक प्राचीन गांव है। इस मंदिर में दूर-दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में...हिमाचल प्रदेश के शिमला में जुब्बल-कोटखाई तहसील में माता हाटेश्वरी मंदिर स्थित है। यहां पर हाटकोटी मां की पूजा की जाती है। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी उनके सभी दुखों का निवारण करती हैं। वहीं मंदिर के गर्भगृह में मां हाटकोटी की एक विशाल मूर्ति है। जोकि महिषासुर का वध कर रही हैं। यही वजह है कि हाटकोटी मां को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां का दाहिना पैर भूमिगत है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में भगवान शिव का एक मंदिर भी स्थापित है। बता दें कि मंदिर के प्रवेश द्वार के बाई ओर विशाल कलश को जंजीर से बांधकर रखा जाता है। जिसको स्थानीय भाषा में चरू कहा जाता है। लोक मान्यताओं के मुताबिक जब भी पब्बर नदी में बाढ़ की स्थिति बनने लगती है, तो यह कलश काफी जोर-जोर से सीटियां भरता है और भागने की कोशिश करता है। जिसके वजह से मंदिर के कलश को जंजीर से बांधकर रखा जाता है। बताया जाता है कि मंदिर में एक और कलश भी हुआ करता है, जोकि भाग निकला। लेकिन मंदिर के पुजारी ने दूसरे कलश को पकड़ लिया और जंजीरों से बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर में स्थित कुछ स्मारक पांडवों द्वारा बनाए गए थे। पौराणिक मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पर पांडवों का आना हुआ था। इस दौरान उन्होंने यहां पर कुछ समय बिताया था।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा । RNI No. MPHIN/2016/68059